

अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने सारे घोड़े खोल दिये गांधी परिवार के बचाव में

इन दोनों की दलील थी, कोई जुर्म नहीं हुआ, कोई पैसे का लेन-देन नहीं हुआ, किसी को कुछ भी भुगतान नहीं हुआ

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 अप्रैल। नैशनल

हेरल्ड केस में कांग्रेस नेताओं, राहुल, सोनिया गांधी तथा अन्य के खिलाफ दाखिल चार्ज शीट को लेकर कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा टकराव की मुद्रा में आ गये हैं। कांग्रेस ने दिल्ली सहित, पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन किये। दिल्ली में पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन ई.डी. कार्यालय की ओर नहीं बढ़ पाये, क्योंकि उन्हें रोकने के लिये, वहाँ भारी पुलिस बल तैनात था।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी तथा जयराम रमेश ने गांधी परिवार के बचाव में पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने कहा कि कोई अपराध नहीं हुआ, पैसे का कोई लेन-देन नहीं हुआ, किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया तथा ए.जे.एल. एवं यंग इंडियन या अन्य

■ कांग्रेस ने दिल्ली में व देश के कई स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित किये, नैशनल हैरल्ड के मामले में ई.डी. द्वारा राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ राज़्ड एवेन्यु कोर्ट में चार्ज शीट दायर करने पर।

■ भाजपा का नेतृत्व अब यह आंक रहा है कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ कार्यवाही करने पर, जनता में क्या प्रतिक्रिया होगी।

■ सवाल यह उठ रहा है कि ऐसी क्या आवश्यकता थी यंग इंडिया का गठन करने की तथा पचास लाख रूपए देकर कंपनी की पुरानी सभी देनदारियाँ खरीदने की? और क्या, यह सब जोखिम उठाने के बाद, गांधी परिवार, नैशनल हैरल्ड की हजारों करोड़ रूपए की सम्पत्ति को कंट्रोल करने में सफल होगा?

किसी के भी बीच कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ।

हालांकि, कांग्रेस बार-बार यह कह रही है कि कोई गलत काम नहीं

हुआ, फिर भी, राज़्ड एवेन्यु कोर्ट में चार्ज शीट पेश कर दी गई है तथा 25 अप्रैल को केस की सुनवाई होनी है। गांधी परिवार को जमानत के लिये

कोर्ट में अर्जी लगानी होगी तथा आरोप तय किये जायेंगे और ई.डी. ने कहा है कि वह अतिरिक्त चार्ज शीट और पेश करने वाली है।

राजनैतिक हलकों में दोष-सिद्धि (कनविकशन) तथा गिरफ्तारी की चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा नेतृत्व भी इस बात का आकलन कर रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी के मुद्दे पर जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रश्न यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर यंग इंडियन बनाने की जरूरत क्या थी, और क्या कांग्रेस नेतृत्व ने 50 लाख रूपए दिये, 90 करोड़ रूपए का कर्ज खरीदा तथा ऐसा करके क्या कांग्रेस नेतृत्व अब इस स्थिति में है कि वह हजारों करोड़ की नैशनल हैरल्ड सम्पत्तियों को नियंत्रित कर सके।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर ई.डी. गांधी परिवार को दोषी सिद्ध करना चाहती है, तो उसे इसके साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

जस्टिस गवई 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शीर्ष अदालत के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने न्यायमूर्ति गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। यदि मंजूरी मिली तो न्यायमूर्ति गवई 14 मई, 2025 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद अपनी सेवानिवृत्ति

■ **वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें उत्तराधिकारी नामित किया।**

23 नवंबर, 2025 तक इस पद पर बने रह सकते हैं। न्यायमूर्ति खन्ना का मुख्य न्यायाधीश पद का कार्यकाल 13 मई, 2025 तक है।

इसके बाद वे सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। न्यायमूर्ति गवई को 24 मई, 2019 को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। परंपरा के अनुसार, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले सरकार को अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफािश भेजते हैं।

दादी के सामने पोते की गर्दन पकड़कर ले गई बाधिन

रणथंभौर में गणेश मंदिर मार्ग पर झाड़ियों में बैठी सुल्ताना बाधिन अचानक बाहर आई, बच्चे की गर्दन को मुँह में दबाया और झाड़ियां में ओझल हो गई

- दो घंटे के प्रयास के बाद वन अधिकारी बाधिन को हटा कर बच्चे का शव ले पाये।
- बूंदी के गाँव की रहने वाली दादी अपने पोता-पोती के साथ त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में शादी का निमंत्रण देने आई थी।

सवाईमाधोपुर, 16 अप्रैल (निस)। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर रास्ते में बुधवार को झाड़ियों में छिपी बैठी बाधिन सुल्ताना 7 साल के बच्चे को उठा ले गई।

वर्नविभाग की टीम और अफसर जंगल की ओर दौड़े, साथ ही गणेश मंदिर मार्ग को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया। इस दौरान झाड़ियों के बीच बाधिन काफी देर तक बच्चे के पैर



रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग में बाधिन ने हमला कर सात साल के बच्चे को मार डाला। बाधिन के हमले से कुछ समय पहले ही चित्र में नज़र आ रहा बच्चा, कार्तिक सुमन बंदर के साथ फोटो खिंचवा रहा था।

पर पंजा रखकर बैठी रही। करीब दो घंटे बाद वन विभाग ने बाधिन को वहां से हटाकर बच्चे के शव को बरामद किया। मृतक बच्चे की पहचान कार्तिक सुमन (7) पुत्र द्वा्रक़ा माली निवासी गोहटा

थाना देई खेड़ा (बूंदी) के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शी राम सिंह ने बताया कि दोपहर 3 बजे श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। वे मंदिर की तरफ से दर्शन कर पैदल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकल पट्टा प्रकरण में रिविज़न याचिका वापस लेने पर बहस पूरी हुई

जयपुर, 16 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य अफसरों से जुड़े एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पूर्व में पेश रिवीजन याचिका को वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों

■ **अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने हाई कोर्ट में कहा कि मौजूदा राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केस आगे बढ़ाना चाहती है।**

की बहस पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस एमएस श्रीवास्तव ने प्रार्थना पत्र पर अपना फैसला बाद में देना तय किया है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 अप्रैल। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक गतिरोध के बीच, सुपर लग्जरी गुड्स मार्केट में एक नया मोर्चा चुपचाप खुल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अमेरिकी फर्मी पर उत्पादन को वापस अमेरिका में लाने का दबाव बना रहे हैं और साथ ही चीनी आयात पर भारी शुल्क लगा रहे हैं। ऐसे में चीन के सप्लायरों ने पलटवार करने के लिए सोशल मीडिया को चुना है। ये लोग सार्वजनिक रूप से यह खुलासा कर रहे हैं कि कैसे वे दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के लिए लग्जरी गुड्स

- बरकिन, लुई विटों, शनैल, एस्टी लॉडर व बॉबी ब्राउन जैसे लग्जरी ब्रॉण्ड के बैग अमेरिका में रिटेल में 29-30 लाख रुपये में बिकते हैं।
- पर, अधिकतर ये आइटम चीन में ही बनते हैं तथा इनकी कुल लागत 1.2 लाख रूपए ही आती है।
- चीन के व्यापारी अब ये आइटम, बिना “ब्रॉण्ड टैग” के 1.2 लाख रुपये में सीधे ग्राहक को बेच रहे हैं। ये व्यापारी ग्राहक को यह भी समझाते जा रहे हैं कि इन आइटम्स में लगे माल की कीमत क्या है तथा चीन के कारीगरों के हुनर की कीमत को भी जोड़ दिया जाये तो भी बनाने का खर्च बिक्री के दाम का दसवां हिस्सा ही होगा।
- बाकी सारा पैसा अमेरिका के व्यापारियों का मार्क-अप व विज्ञापन खर्च हैं।
- इस रणनीति से ग्राहक के मन में लग्जरी आइटम की घनघोर मुनाफा गिरी तो सामने आयी ही, साथ ही चीन के कारीगरों के हुनर व मेहनत का जायका भी देखने को मिला ग्राहक को। इससे, चीन का माल घटिया होने की छवि भी अपने आप खत्म होने लगी है।

बनाते हैं और उन्हीं उत्पादों को अब सीधे

उपभोक्ताओं को उनकी खुदरा कीमतों

से बहुत ही कम कीमत में बेच रहे हैं।

एक डिजिटल आक्रमण, जो गति

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा

जयपुर, 16 अप्रैल। ज़िले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17.6 साल की नाबालिग के साथ समय-समय पर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामस्वरूप को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 2.50 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र अट्वासिया ने अपने आदेश में कहा कि यौन अपराध बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाने के बजाए उसे उचित दंड देना

■ **पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्त पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।**

ज़रूरी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 14 जनवरी, 2022 को कालांडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 दिसंबर, 2021 को स्कूल जाते समय अभियुक्त उसे रास्ते से अपने साथ जबर्न हिंगोनिया ले गया और दुष्कर्म कर वापस छोड़ दिया। इसके बाद 11 जनवरी, 2022 को वह स्कूल से लौट रही थी तो अभियुक्त उसे रास्ते में मिला और साथ जाने के लिए मजबूर करने लगा। इस दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग और उसके परिजन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अन्नाद्रमुक चुनाव जीतने के बाद स्वयमेव सरकार बनायेगी, यह गठबंधन की सरकार नहीं होगी’

अन्नाद्रमुक नेता, पलानीस्वामी की इस घोषणा से भाजपा काफी स्तब्ध!

■ अभी तक भाजपा के स्थानीय नेता बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि एनडीए, जिसमें अन्नाद्रमुक भी शामिल है, तमिलनाडु में सरकार बनायेगा। पर, यह भी सच है कि अमित शाह ने अन्नाद्रमुक के एनडीए में शामिल होने के बाद यह जरूर कहा था कि अन्नाद्रमुक ने एनडीए में शामिल होते समय कोई शर्त नहीं रखी है।

■ पर, वक्त बोर्ड का संशोधित विधेयक संसद में पारित होने के बाद, शायद अन्नाद्रमुक ने यह कहा कि यदि अन्नाद्रमुक-भाजपा के साथ मिलजुल कर सरकार बनायेगी, तो उसे मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा। अतः राजनीतिक मजबूरी के कारण, अन्नाद्रमुक को यह घोषणा करनी पड़ी कि उसका व भाजपा का साथ केवल चुनाव जीतने तक ही है, यह साथ सरकार बनाने के लिए नहीं है।

दरअसल, भाजपा के साथ हुये गठबंधन का अन्नाद्रमुक के अंदर जो विरोध हो रहा है, उससे पलानीस्वामी इस समय भारी तनाव में हैं।

अन्नाद्रमुक के नेता, अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिक्रिया के कारण भी परेशान हैं, क्योंकि भाजपा के साथ हुये गठबंधन के कारण अन्नाद्रमुक को अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिलेंगे।

बुधवार को जब विधानसभा में बोलने की अनुमति नहीं दिये जाने के विरोध में पलानीस्वामी ने वॉकआउट का नेतृत्व किया, उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह गठबंधन तो केवल चुनावों के लिये है तथा अगले वर्ष होने वाले चुनावों में अगर गठबंधन की जीत होती है तो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री द्वारा कटरा-श्रीनगर वंदे भारत का “लांच” स्थगित हुआ

सरकार की ओर से आयोजन को आगे खिस्काने का अधिकृत कारण मौसम की खराबी बताया जा रहा है

- पर, यह आम चर्चा में है, कि स्थगित होने का असली कारण है, आतंकवादी गतिविधियों के कारण असुरक्षा का माहौल।
- जैसा, कि विदित ही है, सिक्युरिटी एजेंसियां ऊधमपुर, कथुआ व पुंछ जिलों में हाई-अलर्ट की स्थिति में हैं।
- सोमवार को ही सुरक्षा एजेंसियों ने भारी कॉर्डन ऑफ किया, सुरनकोट तहसील के लसाना गांव में आतंकवादियों के छुपे होने की खबर के बाद।

लिए हाई अलर्ट पर हैं।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, सोमवार को पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के लस्साना गांव में आतंकी गतिविधियों की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

प्रस्तावित यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को विनाब रेल पुल और अंजी खड्ड रेल पुल का दौरा करना

था, जिसके लिए दो हेलीपैड तैयार किए गए थे।

प्रधानमंत्री को श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के एक विशेष कश्मीर संस्करण को हरी झंडी दिखायी थी। कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में अनेक विशेषताएं होंगी, जैसे हीटिंग सिस्टम और ट्रेन इंजन की विंडस्क्रीन पर एंडी-फॉग सुविधा। इस नई ट्रेन का

ट्रायल भारतीय रेल द्वारा 23 जनवरी को किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि उद्घाटन के लिए नई तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन संभावना है कि यह अप्रैल के अंत तक किया जाएगा।

कश्मीर लाइन, जिसे उधमपुर-श्रीनगर-बaramulla रेल लाइन के नाम से जाना जाता है, 272 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 119 किलोमीटर सुरंगें शामिल हैं।

इस परियोजना में विश्व का सबसे ऊँचा रेल पुल, विनाब ब्रिज और भारत का पहला केबल-स्टेड रेल पुल, अंजी खड्ड ब्रिज शामिल हैं।

पहली बार ट्रेन में एटीएम लगा

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। ट्रेन में सफर करते वक़्त अगर नकदी पास न हो तो हर कोई चिंतित हो जाता है। लेकिन, अब इस चिंता से रेलवे मुक्ति दिलाने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस को देश की पहली ऐसी ट्रेन बना दिया है, जिसमें एटीएम लगा हुआ है। ट्रेन के एसी कोच में लगे इस एटीएम से चलती ट्रेन में ही यात्री कैश निकाल सकते हैं। इस एटीएम

■ **यदि अच्छा रिस्रॉन्स मिला तो लम्बी दूरी की अन्य ट्रेनों में भी एटीएम लगाये जायेंगे।**

को खास तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि यह ट्रेन के पूरी रफ्तार में होने के बावजूद भी ठीक से काम कर सके। साथ ही इसे चोरों से बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं और इस पर चौबीस घंटे सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी। रेलवे का कहना है कि अगर मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगे एटीएम को अच्छा रिस्रॉन्स मिलता है तो फिर लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों में भी एटीएम लगाए जाएंगे।

यह नई सुविधा भुसावल रेलवे डिवाजन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साझेदारी में शुरू की गई है और इसका ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

विचार बिन्दु

पागल, प्रेमी और कवि की कल्पनाएँ एक सी होती हैं। –शेक्सपियर

राजस्थानी भाषा में प्राथमिक शिक्षा का आगाज: विलम्ब से ही सही उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम

राजस्थान सरकार ने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में राजस्थानी भाषा माध्यम से इसी सत्र से पढाई शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो शिक्षा, संस्कृति और बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। कहते हैं जब जागो तब सवेरा, हालांकि यह कदम राज्य सरकार को बहुत पहले उठाना चाहिए था।

आजादी से पहले राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से गुरुकुल, पाठशाला, और धार्मिक संस्थानों तक सीमित थी। राजस्थानी भाषा में शिक्षा का प्रचार-प्रसार ज्यादा व्यवस्थित नहीं था। उस समय राजस्थानी को बोलचाल और साहित्य की भाषा के रूप में तो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन औपचारिक शिक्षा में संस्कृत, फ़ारसी, और बाद में अंग्रेजी का बोलबाला आ गया था। आज हालात ये हैं कि हिन्दी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली ने एक उम्र के बाद बच्चों को उनकी मातृभाषा से काट कर काफी दूर कर दिया है। आज के इस डिजिटल युग में राजस्थानी भाषा में ब्लॉग, वेबसाइट्स, और सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर कुछ जागरूकता बढ़ी है। कुछ गैर-सरकारी संगठनों और साहित्यकारों ने राजस्थानी में पाठ्य सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। राजस्थान सरकार ने समय-समय पर राजस्थानी को स्कूलों में पढाने की घोषणाएँ तो कीं, लेकिन इसे पूरी तरह कभी भी लागू नहीं किया गया।

फ़िलहाल राज्य सरकार यह योजना प्राथमिक आधार पर नौ जिलों-सिरोही, डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़-में शुरू करने जा रही है और 2026 तक इसे 25 जिलों में विस्तार दिया जाएगा। वैसे तो यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही है, जो कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा की वकालत करती है। यूनेस्को की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, मातृभाषा में पढाई बच्चों की सीखने की क्षमता को 30-40 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूँढाड़ी, मालवी, बागड़ी, शेखावाटी, ढूँढाड़ी और बूज जैसी उप-बोलियों में बंटी है। यह भाषा अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को यह योजना इसे राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की दिशा में अवश्य मदद करेगी। इस भाषा के आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए व्यापक उपयोग होना पहली शर्त है। समृद्ध साहित्य और शैक्षिक उपयोग जैसे मानदंड भी जरूरी हैं, जिन पर राजस्थानी भाषा खरी उतरती है। इसके समृद्ध साहित्यिक का इतिहास प्राचीन है, जिसमें ‘पृथ्वीराज रासो’ और चारण काव्य शामिल हैं। ऐसे में स्कूलों में राजस्थानी माध्यम से पढाए जाने से इसका शैक्षिक महत्व बढ़ेगा, जिससे मान्यता की मांग को बल मिलेगा और केंद्र सरकार पर अच्छा खासा दबाव होगा। मणिपुरी और बोडो जैसी भाषाओं को भी शिक्षा में उपयोग के बाद मान्यता मिली थी और राजस्थानी के लिए भी यह संभव हो सकेगा।

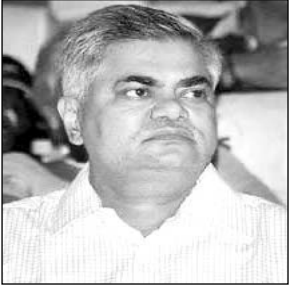
इस योजना के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ बच्चों का व्यक्तित्व विकास है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मातृभाषा में पढाई से बच्चे आत्मविश्वास और रचनात्मकता में बढ़ोतरी महसूस करते हैं। अपनी भाषा में पढने से वे बिना भाषाई बाधा के विचार व्यक्त करते हैं, जिससे आत्मसम्मान बढ़ता है। यह ग्रामीण बच्चों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, जो हिंदी या अंग्रेजी में असहज होते हैं। अपनी संस्कृति से जुड़ाव सांस्कृतिक गौरव पैदा करता है, जो व्यक्तित्व को मजबूत करता है। मातृभाषा में पढाई जटिल अवधारणाओं को समझने में आसान बनाती है, जिससे तार्किक और रचनात्मक सोच विकसित होती है। स्वीडन और एनाडा में मातृभाषा आधारित शिक्षा ने शैक्षिक प्रदर्शन में बहुत सुधार दिखाया था। राजस्थान में भी ऐसा प्रभाव संभव है। यह योजना सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान देगी जिससे राजस्थानी लोक गीत, कहानों और कथाएँ नई पीढ़ी तक पहुँचेंगी। इससे ड्रॉपआउट दर को कम

होगी क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में पढाई से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। रोजगार के अवसर तो निश्चित ही बढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थानी के शिक्षकों और शिक्षण सामग्री निर्माताओं की मांग बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी सामाजिक एकता को बढ़ावा मिला, क्योंकि अपनी भाषा से जुड़ाव आपसी समझ और सम्मान को प्रोत्साहित करती है। यह योजना सामाजिक समावेशता भी बढ़ाएगी, खासकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में, जहां बच्चे अक्सर हिंदी या अंग्रेजी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। हालांकि, चुनौतियाँ बहुत हैं इसे लागू करने में। राजस्थानी में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी पहले से ही एक समस्या है, और विशेष प्रशिक्षण की जरूरत इसे और जटिल बना देगी। सरकार को गहरे और लम्बे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने होंगे। पाठ्य सामग्री की कमी भी एक मुद्दा रहेगा जिसे समय रहते हल करना आवश्यक है। मानकीकृत पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति चाहिए। हालांकि इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं लेकिन उनका परीक्षण और मूल्यांकन तो तभी सामने आएगा जब बच्चे इसे ग्रहण करेंगे। राजस्थानी में उप-बोलियों के बीच सामंजस्य बिठाना चुनौतीपूर्ण है। एक सामान्य पाठ्यक्रम बनाना होगा, जो सभी बोलियों को समावेशी बनाए। अभिभावकों की मानसिकता भी बदलनी होगी, क्योंकि कई लोग अंग्रेजी या हिंदी को प्राथमिकता देते हैं।

अब तो ठेठ ग्रामीण इलाकों में भी अंग्रेजी के प्रति व्यामोह ने गहरी धुंध बना दी है। इसके लिए जागरूकता अभियान जरूरी है। निजी स्कूलों का रवैया एक बड़ी बाधा है। राजस्थान में निजी स्कूल अक्सर अंग्रेजी या हिंदी को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अभिभावक इसे आधुनिक मानते हैं। सरकार राजस्थानी भाषा माध्यम शिक्षण को प्रोत्साहन दे सकती है, जैसे वित्तीय सहायता या मान्यता में लाभ। राजस्थानी को एक विषय के रूप में पढाने का मॉडल अपनाया जा सकता है, जैसा कर्नाटक में कन्नड़ के साथ हुआ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन सहयोगात्मक दृष्टिकोण बेहतर होगा। निजी स्कूलों के लिए प्रशिक्षण और सामग्री उपलब्ध करानी होगी। भारत के अन्य राज्यों में मातृभाषा आधारित शिक्षा की स्थिति अलग-अलग है। कर्नाटक में कन्नड़ प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य है, और निजी स्कूल भी इसे पढाते हैं। यूडीआरएसई की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 53.5 प्रतिशत से अधिक छात्र कन्नड़ में पढते हैं, जो मातृभाषा शिक्षा का सशक्त उदाहरण है। तमिलनाडु में तमिल प्राथमिक स्तर पर मुख्य माध्यम है, जिससे बच्चों का सीखना आसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 89.9 प्रतिशत छात्र बंगाली में पढते हैं, जो मातृभाषा शिक्षा का सशक्त उदाहरण है। असम में 91.1 प्रतिशत असमिया भाषी छात्र अपनी भाषा में पढते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच बढ़ी है। ओडिशा में संथाली, हो, मुंडारी और कुड़ुख जैसी जनजातीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षकों और सामग्री की कमी बाधा है। गुजरात में गुजराती मुख्य माध्यम है, जिससे बच्चों की समझ में सुधार हुआ है। केरल में मलयालम प्राथमिक शिक्षा में प्रचलित है, और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में हल्बी और सरगुजिया जैसी स्थानीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री विकसित की गई है। हालांकि, उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी और अंग्रेजी का दबदबा है, और भोजपुरी, मैथिली जैसी बोलियाँ शिक्षा में उपेक्षित हैं। मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में गोंडी और भीली में पढाई शुरू हुई है, लेकिन यह सीमित है। एक राजस्थानी कहावत है, “**ज्यू नींव पक्की, त्यू मकान सम्पन्न**”। यह शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को दर्शाती है। मातृभाषा में पढाई बच्चों की नींव को मजबूत करती है, जो उनके भविष्य को स्थायी बनाती है।

चूँकि राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जिससे इसे आधिकारिक मान्यता और संसाधन नहीं मिले। स्कूलों में राजस्थानी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने में कमी रही। हिंदी और अंग्रेजी के दबाव में राजस्थानी शिक्षा हाशिए पर रही। मानकीकृत व्याकरण और शब्दकोश के अभाव में भाषा का शैक्षिक विकास रुका गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और शहरी क्षेत्रों में हिंदी-अंग्रेजी की प्राथमिकता ने राजस्थानी के उपयोग को बहुत कम किया है। यह योजना राजस्थानी को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। चुनौतियों का समाधान जरूरी है। पाठ्य सामग्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय लेखकों को शामिल किया जाना चाहिए। उप-बोलियों के लिए लचीला पाठ्यक्रम चाहिए। जागरूकता के लिए सामुदायिक रेडियो और सोशल मीडिया प्रभावी उपयोग होना चाहिए। निजी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करना होगा। अन्य राज्यों के अनुभव, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु, मार्गदर्शक दे सकते हैं। यह प्रयास बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ेगा, राजस्थानी को मान्यता दिलाएगा और सांस्कृतिक विरासत को बचाएगा।

—अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र मोहन शर्मा, साहित्यकार, शिक्षाविद और चिन्तक



राजेश्वर सिंह

नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण, सक्रिय, समृद्ध व सुखद अस्तित्व का सुनिश्चयन कैसे हो, इस संबंध में प्रत्येक संवेदनशील, जागरूक व विचारशील व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में एक सुचिंतित, सुविचारित व सुनिश्चित अवधारणा होती है, जिसे हम उस व्यक्ति विशेष की विचारधारा के रूप में अभिहित करते हैं। समान विचारधारा के लोग नीति और कार्यक्रम के आधार पर संगठित होकर राजनीतिक दल को जन्म देते हैं। आदर्श रूप में प्रत्येक राजनीतिक दल में खुली सदस्यता, आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक विचार विमर्श द्वारा लोक नीति का निर्धारण, विचारधारा, नीति एवं कार्यक्रम के संबंध में कार्यकर्ता प्रशिक्षण की प्रणाली तथा लोक शिक्षण एवं लोक जागरण हेतु प्रचार- प्रसार और सघन

जनसंपर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वातंत्र्य पूर्व और स्वातंत्र्योत्तर भारत में जिन राजनीतिक दलों का गठन हुआ ,उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ,जनता दल के विभिन्न टुकड़ों तथा आम आदमी पार्टी को एक समूह में, सीपीआई,सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक व रिवांशलिन्गुनी सोशलिस्ट पार्टी को दूसरे समूह में, भारतीय जन संघ, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद तथा वर्तमान में सक्रिय भारतीय जनता पार्टी को तीसरे समूह में ,शिवसेना व अकाली दल इत्यादि को चौथे समूह में तथा डीएमके, एआईडीएमके, असम गण परिषद इत्यादि को पांचवे समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें वामपंथी दल जहां कार्यकर्ता आधारित (काडर बेस्ड) हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आधारित (मास बेस्ड) है, वहीं भाजपा में दोनों ही पद्धतियों का संमिश्रण है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिनियुक्त पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं तथा पार्टी के अंशकालिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनता है।

भारत के राजनीतिक दलों में ग्राम पंचायत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक खुली सदस्यता व संगठनिक चुनाव पर आधारित आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना दिवास्वप्न ही

है। पदाधिकारियों के कार्यकाल पर अधिकतम अवधि का सीमारोपण नहीं होना सबसे बड़ा दृषण है, जिससे विभिन्न दलों में व्यक्तिवाद और परिवारवाद की दुष्प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

मेरी विनम्र राय में प्रत्येक राजनीतिक दल की प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय निकाय तक निर्वाचित अध्यक्षों को अधिकतम को दो कार्यकाल से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए और यही सिद्धांत सरपंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर,मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री पर भी लागू होना चाहिए।

मुझे अमरीकी राष्ट्रपति प्रणाली की यह सबसे बड़ी विशेषता प्रतीत होती है जिसे भी वहां का वर्तमान तंत्र ध्वस्त करने की योजना बना रहा है। प्रत्येक राजनीतिक दल को जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, रक्षा, विदेश नीति, सामाजिक न्याय व समावेशी विकास आदि के संबंध में अपनी रीति नीति स्पष्ट करनी चाहिए व इस संबंध में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना चाहिए।

इस व्यवस्थित तंत्र में स्थानीय स्तर पर कार्यरत पुस्तकालय व वाचनालय, स्टडी सर्किल, विचार गोष्ठी, पत्र- पत्रिकाओं का

प्रकाशन, प्रमुख विचारकों की जयंती एवं पुण्यतिथि आयोजित करना तथा इस माध्यम से पार्टी की विचारधारा, नीति एवं कार्यक्रम का प्रचार- प्रसार इत्यादि सम्मिलित किये जा सकते हैं। लोकतंत्र में लोक शिक्षण किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुखतम दायित्व है।

यह तभी संभव है जब राजनीतिक दल जन सामान्य को सचेत व जागरूक बनाने की जिम्मेदारी का वहन करें। भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं व सरकार बनाई जा सकती है पर राष्ट्र व उसके नागरिकों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता।

इसके लिए जन सामान्य का बौद्धिक एवं वैचारिक दृष्टि से सशक्त व समर्थ होना बहुत जरूरी है ताकि वे समुचित चिंतन, मनन व मंथन के उपरांत राष्ट्रीय हित व व्यापक जनहित में सर्वोत्तम राजनीतिक विकल्प का चयन कर सकें।

इसके लिए दलीय कार्यकर्ताओं का पार्टी के सिद्धांत, विचारधारा, नीति एवं कार्यक्रम की बारीकियों में निष्णात होना तथा उनके द्वारा सघन जनसंपर्क का कार्यक्रम हाथ में लिया जाना न केवल आवश्यक है अपितु अनिवार्य भी है।

इसी प्रकार पंचायती राज

संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों से लेकर विधानमंडलीय एवं संसदीय चुनाव तक के प्रत्याशियों के चयन में दल की विधिवत निर्वाचित स्थानीय इकाइयों की सक्रिय, सशक्त व निर्णायक भूमिका होनी चाहिए।

पार्टी हाईकमान द्वारा ऊपर से प्रत्यक्षी थोपा जाना न केवल पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान है वरन यह पार्टी कार्यकर्ताओं में धरातल पर जन समस्या समाधान में प्रवृत्त होने के बजाय बड़े नेताओं की परिक्रमा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। यदि हमें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमूलचूल सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन करना है तो यह आवश्यक है कि विभिन्न लेखक, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी व सिविल सोसाइटी समूह उपर्युक्त बिंदुओं पर व्यापक जन जागरण व जनमत निर्माण हेतु पहलकदमी करें तथा अंततः सर्व दलीय बैठक के माध्यम से सर्व सहमति का निर्माण हो ताकि देश एवं दलों के संविधान में तदनुसार संशोधन किया जा सके व उक्त प्रारूप को अमलीजामा पहनाया जा सके।

राजेश्वर सिंह, आईएएस (अवकाश प्राप्त)

राजस्थान में उच्च शिक्षा का स्वरूप



अशोक कुमार

राजस्थान में उच्च शिक्षा का स्वरूप विविधतापूर्ण और विकासशील है। यहां विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थान मौजूद हैं, जिनमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान, चिकित्सा संस्थान और कृषि संस्थान शामिल हैं।

विश्वविद्यालय:- राजस्थान में कई सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हैं, जो विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। इन विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा और अन्य व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम शामिल हैं।

राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के नाम निम्नलिखित हैं: सामान्य विश्वविद्यालय: राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर,जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, महाराजा सूरजमल बूज विश्वविद्यालय, भरतपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवरविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा!

महाविद्यालय:- राजस्थान में बड़ी संख्या में सरकारी और निजी महाविद्यालय हैं, जो विभिन्न विषयों में स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। ये महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से संबद्ध होते हैं और उनके पाठ्यक्रम का पालन करते हैं।

तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा,बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा। तकनीकी संस्थान इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और अन्य तकनीकी विषयों में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान

करते हैं।

चिकित्सा संस्थान: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर! चिकित्सा संस्थान चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं।

कृषि संस्थान: महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर,श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, विश्वविद्यालय, जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा। कृषि संस्थान कृषि, पशुपालन और अन्य कृषि विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं।

संस्कृत विश्वविद्यालय: जगद्गुरु रामानंदचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर,

विधि विश्वविद्यालय: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर !

खुला विश्वविद्यालय: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा !

अन्य विश्वविद्यालय: सरदार पटेल पुलिस, सूक्ष्म और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान क्रीडा विश्वविद्यालय, झुंझुनू, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर ,राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर !

इसके अतिरिक्त, राजस्थान में कई निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय भी हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा की कुछ विशेषताएं: राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कई पहल की गई हैं।

राजस्थान में उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा की कुछ चुनौतियाँ:-

राजस्थान में उच्च शिक्षा में नामांकन दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं:- सामाजिक-आर्थिक कारक: राजस्थान में गरीबी और सामाजिक असमानता उच्च शिक्षा तक पहुँच को

सीमित करती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। लड़कियों की शिक्षा को अक्सर प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जिससे उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी कम हो जाती है।

शिक्षा की गुणवत्ता: कुछ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, जिससे छात्रों का रुझान कम हो जाता है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों की कमी भी नामांकन दर को प्रभावित करती है।

बुनियादी ढांचा: कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँचने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है। दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों की कमी भी उच्च शिक्षा तक पहुँच को सीमित करती है।

सरकार के प्रयास:-राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही है, जिनमें शामिल हैं: नए उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना।मौजूदा संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना।छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना।व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

इन प्रयासों के बावजूद, राजस्थान में उच्च शिक्षा में नामांकन दर को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करने, राज्य न केवल अपने छात्रों के भविष्य को बेहतर बना सकता है, बल्कि अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दे सकता है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं: अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:अनुसंधान और नवाचार का महत्व: आर्थिक विकास: अनुसंधान और नवाचार से नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है। सामाजिक विकास: अनुसंधान से सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने में मदद मिलती है।यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।शैक्षिक विकास: अनुसंधान से ज्ञान का विस्तार होता है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है।यह छात्रों को आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है।

राजस्थान में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदम: निवेश में वृद्धि: अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी और निजी निवेश में वृद्धि आवश्यकता: उद्योग की

आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रमों को उद्योग की प्राथमिकताओं के अनुसार अद्यतन करना चाहिए। व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों को इंटरनशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना चाहिए।

रोजगार योग्यता: छात्रों को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। नई तकनीकी शिक्षा भी जोर देना चाहिए।

सामाजिक प्रासंगिकता: शिक्षा को सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए।छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकता के मूल्यों को सिखाना चाहिए।

सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम:सरकारी नीतियाँ: उच्च शिक्षा में सुधार के लिए स्पष्ट और प्रभावी नीतियाँ लागू करना चाहिए।उच्च शिक्षा संस्थानों की अधिक स्वायत्तता और जवाबदेही देनी चाहिए।शिक्षा में निजी निवेश को भी बढ़ावा देना चाहिए।

शैक्षिक संस्थान: शैक्षिक संस्थानों को गुणवत्ता सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।अध्यापकों और छात्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करके, राज्य न केवल अपने छात्रों के भविष्य को बेहतर बना सकता है, बल्कि अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दे सकता है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:अनुसंधान और नवाचार का महत्व: आर्थिक विकास: अनुसंधान और नवाचार से नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है। सामाजिक विकास: अनुसंधान से सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने में मदद मिलती है।यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।शैक्षिक विकास: अनुसंधान से ज्ञान का विस्तार होता है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है।यह छात्रों को आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है।

राजस्थान में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदम: निवेश में वृद्धि: अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी और निजी निवेश में वृद्धि आवश्यकता: उद्योग की

रानी चाहिए। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को पर्याप्त धन उपलब्ध करना चाहिए।अवसरबन का विकास:आधुनिक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहिए। सहयोग को बढ़ावा देना: विश्वविद्यालयों, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित करनी चाहिए।उद्यमिता को प्रोत्साहित करना: छात्रों और शोधकर्ताओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों को समर्थन देना चाहिए। नीतियों का निर्माण: अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियाँ बनानी चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों की संरक्षित करने के लिए उपाय करने चाहिए।

प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास: अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षित करना चाहिए। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए करियर के अवसर प्रदान करने चाहिए।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रयास: राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। फिर भी, इस दिशा में और अधिक निवेश और प्रयासों की आवश्यकता है ताकि राज्य एक महत्वपूर्ण अनुसंधान और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित हो सके। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राजस्थान में उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों की फीस एक बड़ी समस्या है। इसके कई कारण हैं और इसके समाधान के लिए कई सुझाव दिए जा सकते हैं।

समस्या के कारण:-अत्यधिक फीस: कई निजी संस्थान अत्यधिक फीस वसूलते हैं, जो अधिकांश छात्रों और उनके परिवारों के लिए वहन करना मुश्किल होता है। कुछ संस्थान तो कैपिटेशन फीस भी लेते हैं, जो गैरकानूनी है। पारदर्शिता की कमी: फीस संरचना में पारदर्शिता की कमी है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को फीस के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है।फीस में अचानक वृद्धि भी एक समस्या है। विनियमन का अभाव: निजी संस्थानों की फीस को विनियमित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव है। सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

—अशोक कुमार,

पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर



पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:40 तक, चर 10:51 से 12:26 तक, लाभ-अमृत 12:26 से 3:37 तक, शुभ 5:12 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:05, सूर्यास्त 6:48

राशिफल

गुरुवार 17 अप्रैल, 2025

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ नक्षत्र शुक्रवार प्रातः 8:21 तक, वारियान योग रात्रि 12:50 तक, बालक कर्ण दिन 3:24 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

मेघ घर-परिवार की परेशानियों के कारण मन में असंतोष बना रहेगा, भागदौड़ रहेगी। आज शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

तुला स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। विवादित मामलों का निपटारे का प्रयास करें। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। नौकरपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

मिथुन व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक यात्रा सक्रिय रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना को दो वर्षों में पूरा करें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल

के कार्यदिशे जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन पैकेज में भूमि अवाप्ति के अवार्ड, वन क्लीयरेंस एवं अन्य क्लीयरेंस के कार्य में गति लाई जाए। उन्होंने इस परियोजना में अब तक

- यमुना जल समझौते की बैठक 20 अप्रैल को, पिलानी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी टास्क फोर्स की बैठक
- भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेषाधिकारियों की होगी नियुक्ति
- ईसरदा पेयजल परियोजना को जून तक किया जाए पूरा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उनके निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

एवं सिंचाई के साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में सरलीकरण सहित अन्य सभी सहायताएं उपलब्ध कराएंगी। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल संसाधन विभाग, इंंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए एवं भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत विवरण एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों

हो चुकी अधिगृहीत भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसी क्रम में डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रैल को यमुनानगर में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रैल को पिलानी में होगी। उन्होंने अधिकारियों को नक्शे एवं अलाइमेंट की डिजाइन की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि परवन वृहद् बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि परियोजना में बांध निर्माण कार्य एवं पाइपलाइन वितरण प्रणाली से लेकर डिग्री एवं पंप हाउस कार्यों में गति लाई जाए। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति निर्बाध हो : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में पेयजल प्रबंधन एवं समर कंटी-जैसी प्लान को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्ययोजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलक्टरों की अनुशंसा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आवश्यकता के अनुसार टैंकों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित पाइपलाइनों, पुराने नलकूप एवं हैडपंप के मरम्मत कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए संचालित राज्य एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के

- ‘फील्ड में रहें अधिकारी, जलापूर्ति व्यवस्था रखें सुचारू’

नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, कंट्रोल रूम में दर्ज होने वाली शिकायतों का प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग कर त्वरित निस्तारण भी किया जाए। उन्होंने बिजली कनेक्शन लेकर नलकूपों एवं टचयूबवैलों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने नलकूपों हेतु भंडार में स्पेयर पंप-मोटर्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि हर ग्राम में पेयजल एवं इससे संबंधित योजनाओं के लिए ग्राम स्तर पर दो जल मित्र बनाए जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका सहयोग लिया जा सके।

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

कम वसूली वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को नोटिस दें : मंजू राजपाल

जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु लाई जा रही मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना

- ‘मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना का करें व्यापक प्रचार-प्रसार’



सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बुधवार को नेहरू सहकार भवन में समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया।

लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किए जा रहे पोर्टल को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। जिन जिलों में अधिक ऋण राशि बकाया है, उनमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग रणनीति बनाई जाए।

बैठक में भूमि विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि योजना की क्रियान्विति के लिए पोर्टल लगभग तैयार किया जा चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। पोर्टल पर ऋणियों की सहूलियत के लिए विभिन्न

सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह पात्र ऋणियों को मैसरे के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही, कॉल सेंटर की स्थापना कर सभी पात्र व्यक्तियों को कॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिन जिलों में अधिक डिमांड है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत

नियमित खातों में कुल 111.98 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 91.04 प्रतिशत है। वहीं, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अवधिपार ऋणों के मामले में समझाइश एवं सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वसूली कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गिव अप अभियान में अब तक 17.52 लाख अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा : गोदारा

- ‘खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ होने से जुड़े 19.70 लाख नए लाभार्थी’
- अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत प्रतिवर्ष होगी

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में जयपुर जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्रों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने, खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के उपरांत नए लाभार्थियों के जोड़ने एवं खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ने हेतु लंबित आवेदनों की स्थिति पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया गया।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाई जाने से प्रदेश के करोड़ों खाद्य सब्सिडी धारकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार र्विचतों के लोगो ने स्वतः खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। इस अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत प्रतिवर्ष होगी। साथ ही संपन्न व्यक्तियों द्वारा खाद्य

अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई ताकि वे समुचित लाभ ले सकें। आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। गोदारा ने कहा कि सक्षम लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने हेतु प्रेरित करने के लिए गत वर्ष शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत आज तक 17.52 लाख अपात्र लोगों ने स्वतः खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। इस अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत प्रतिवर्ष होगी। साथ ही संपन्न व्यक्तियों द्वारा खाद्य

सब्सिडी छोड़ने से बचे हुए अन्न का र्विचत पात्रों को खाद्य सुरक्षा देने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गोदारा ने कहा कि एनएफएसए से नाम हटवाने वाले संपन्न व्यक्ति मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ भी नहीं ले सकेंगे। इससे राज्य सरकार को होने वाली बचत का भी उपयोग वास्तविक हकदारों के कल्याण हेतु किया जा सकेगा। उन्होंने कहा की स्वतः खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वाले सक्षम लाभार्थियों के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाए। राशन वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों पर भी विभागीय अधिकारी उचित कार्रवाई करें।

बैठक में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि संपन्न व्यक्तियों का कर्तव्य है की वह गरीबों के हक में खाद्य सब्सिडी

छोड़ें। उन्होंने कहा की सक्षम लोगों द्वारा छोड़ी गई सब्सिडी गरीब के मुंह का निवाला बनती है। खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़े सभी संपन्न व्यक्तियों को गिव अप अभियान में भाग लेकर इस पुनीत कार्य में पूर्ण सहभागिता निभानी चाहिए।

बैठक में हवा महल विधायक बालमुकुंदचार्य, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, चौमू विधायक शिखा मिल बराला, उपेन यादव, चंद्र मोहन मीणा, सांगानेर प्रधान भंवर कंवर, नगर पालिका चौमू अध्यक्ष विष्णु सैनी, रामपुरा डाबड़ी प्रधान हरदेव यादव, शाहपुर प्रधान मंजू शर्मा, मनोहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता प्रजापत, शाहपुरा नगरपालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी सहित विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र कुमार सोनी, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पुनम सागर सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस ने ई.डी. ऑफिस के बाहर धरना दिया

जयपुर। नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की ओर से पेश चार्जशीट को लेकर कांग्रेस की ओर से देशभर में प्रदर्शन किया गया। इसी सिलसिले में जयपुर में ज्योति नगर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर धरना देते हुए कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई के विरोध में आगे भी सड़कों पर उतरने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया।

- राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्ज शीट का विरोध

धरने में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जुली सहित कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कहा कि हमारी सरकार ने गांधीवादी तरीके से सरकार चलाई। हम भी ऐसे ही कार्रवाई करते तो भाजपा के कई नेता जेल में होते। उन्होंने कहा कि मदन दिलावर पर 14 मुकदमे दर्ज हैं, उनका काम केवल अंगरेज बयानबाजी करना ही है और उसे शिखा जैसा पवित्र महकमा दिया गया है। हमारी सरकार में ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होती तो वो जेल में होते। इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इन एजेंसियों में काम

करने वाले अधिकारियों का ईमान भाजपा के पैरों में रखा हुआ है, हमारे कुछ नेता ईडी के डर से कांग्रेस पार्टी छोड़ गए और जिनके ईमान जिंदा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पंवार पर प्रधानमंत्री ने 70 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था और 7 दिन बाद ही उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तब उन पर खूब आरोप लगाए थे, लेकिन वह भी भाजपा में जाकर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो गए।

धरने में कांग्रेस विधायक इंंदिरा मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा दी है, मुझे जान का खतरा है। भाजपा के लोगों ने एक कार्यक्रम के दौरान मुझ पर हमला किया था, हमारी सरकार की कमी रही की भाजपा के लोगों पर हमारी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने के विधायक रफीक खान, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियाणा, आरटीडी के पूर्व अध्यक्ष धमरेंद्र राठौड़, कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा सहित कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

नेशनल हेराल्ड की संपत्ति खुर्द बुर्द कर देना गांधी परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के देशभर में धरने और प्रदर्शन करने की घोषणा पर कहा कि धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है पर उन्हें जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1937 में नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ था उस समय 5000 शेयर होल्डर थे, यह संपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों की है किसी खानदान की जागीर नहीं है। यह कंपनी जब बन रही थी तब सरदार पटेल ने इसके लिए हो रहे धन संग्रह पर सवाल उठाया था कि जिस तरह से लोगों से पैसा लिया जा रहा है यह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानू गुप्ता ने भी इसके लिए धन इकट्ठा किया था पर जो स्वतंत्रता सेनानियों की प्रॉपर्टी थी वह अब खानदान की प्रॉपर्टी बना दी गई।

राठौड़ ने कहा कि 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया, कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ रुपए दिए। एक राजनीतिक दल

- ‘50 लाख में हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा, 76 फीसदी मां-बेटे की भागीदारी’
- ‘भूल केवल वोट बैंक के लिए के दंगेईयों का साथ दे रही है ममता बेनर्जी’

किसी प्राइवेट बॉडी को लोन नहीं दे सकती, यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जब नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लोन नहीं चुका पाई तो कोर्पोरेट षड्यंत्र करने का ऋण परिवार के पास संपत्ति आ जाए इसके लिए यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई गई।

उन्होंने कहा कि इस कंपनी में 38 फीसदी शेयर सोनिया गांधी के और 38 फीसदी शेयर राहुल गांधी के पास रखे गए। शेष शेयर मोतीलाल बोहरा और ऑस्कर फर्नांडीज जैसे लोगों के पास थे। इस कंपनी पर नाम 9 करोड़ के इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर दिए गए केवल 50 लाख रुपए में। जिस कंपनी को यह शेयर दिए गए उस कंपनी में 76 फीसदी की भागीदारी माता और पुत्र की थी, जिसकी दिल्ली, मुंबई,

बजट घोषणाओं का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : दिलावर



पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया।

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 की विभागीय बजट घोषणाओं के कार्यों का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को समय से घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।

दिलावर आज बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के लम्बित प्रकरणों, कार्यों के क्रियान्वयन एवं अधिकारियों के रात्रि विश्राम के संबंध में

आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करो। उन्होंने स्वामित्व योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई बजट घोषणाओं के लंबित प्रकरणों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों द्वारा किए गए दौरो और रात्रि विश्राम की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में गंदगी पाए

जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्वोटीटी (एफुईएस) के साथ वनस्पति सीड बैंक के संबंध में एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। अंत में बैठक में डॉ. जोगाराम शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुहम्मद जुनैद, निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, सलोनी खेमका, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित थे।

डॉ. गर्ग ने पानी की समस्या का निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए

मंत्री ने लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं पर चर्चा की

भरतपुर 16 अप्रैल। पूर्व मंत्री व जूनून विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने जूनून के दौरे के दौरान शहर के पर्यटन नगर और विजय नगर कॉलोनी में पानी की समस्या की शिकायत के लिए स्थानीय लोगों की पानी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अन्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं पर चर्चा की।

विधायक डॉ. गर्ग ने जूनून के तीसरे दिन मंहगाया, नौह, नगला गोपाल, नौगाया, हथैनी, इकरन, नगला परशुराम, जाट मंडौली सहित शहरी क्षेत्र के विजय नगर, सारं नगर, सारस सहित अन्य क्षेत्रों में प्रवेश द्वारों की यात्रा की। साथ ही वे



पूर्व मंत्री व जूनून विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों के दुख दर्द जाने।

लोगों के दुख-दर्द भी शामिल हैं।

इंटरव्यू नगर और विजय नगर कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या

से परेशान होकर कहा। जिस पर डॉ. गर्ग ने जलदाय विभाग के

- गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की समस्या से संबंधित क्षेत्र में टचयूबेल लगाने के लिए निर्देशित किया।**

अधिकारियों को एमओयू पर क्रिएटर की पोस्ट के बारे में जानकारी ली और गर्मी के मौसम को देखते हुए नोएडा पानी की समस्या से संबंधित क्षेत्र में टचयूबेल पत्रिका के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा डॉ. गर्ग ने विभिन्न वास्तुशिल्प कार्यक्रमों में नव दंपतियों और उनके भव्य कोमों को स्थापित किया।

जैन संतों पर हमला, कठोर कार्यवाही करने की मांग

हमले की घटना से सम्पूर्ण भारत वर्ष के जैन संतों में एवं जैन

धर्मावलंबियों में भारी आक्रोश है

भीलवाड़ा। मध्यप्रदेश मे जैन संतों पर हुए हमले व हमलावरों द्वारा संतों के साथ अमानवीय कृत्य करने के विरोध में जैन समाज के सदस्यों जैन कॉंग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष आनंद चपलोट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने की माँग की। ज्ञापन मे बताया की मध्यप्रदेश के सिंगोली के पास कछाला बस स्टैण्ड के आगे हनुमान मन्दिर पर जैन संत बलभद्र मुनि, शैलेश मुनि, मुनीन्द्र मुनि रात्रि

जेईई-मेन एआईआर-1 परीक्षा नौ पारियों में संपन्न हुई

कोटा, (निसं)। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन (बीई-बीटेक) जो कि इस वर्ष 22 से 29 जनवरी के मध्य 10 तथा अप्रैल माह में 2 से 8 अप्रैल के मध्य 9 पारियों में संपन्न हुई। दोनों पारियों में मिलाकर इस वर्ष इतिहास में सर्वाधिक 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई-मेन परीक्षा दी, परीक्षा का परीगमन ऑल इंडिया रैंक के साथ 17 अप्रैल को जारी किया जाना संभावित हैं। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसिलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष जेईई-मेन के जारी किए गए परीगमनों में आल इंडिया रैंक-1 पर कई

स्टूडेंट्स आना तय है। इसका कारण जेईई-मेन द्वारा दो विद्यार्थियों के समान टोटल एनटीए स्कोर पर टाई लगने का मैथ्ड्स है। एनटीए द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार दो विद्यार्थियों के टोटल एनटीए स्कोर पर टाई लगने पर सर्वप्रथम मैथैमेटिक्स का एनटीए स्कोर, इसमें टाई होने पर फिजिक्स, इसके बाद कैमेस्ट्री के एनटीए स्कोर के आधार पर रैंक को प्राथमिकता दी जाएगी। उपरोक्त सभी विषयों में टाई लगने की स्थिति में विद्यार्थियों के कुल सही एवं गलत जवाबों के प्रातांकों के अनुपात को देखा जाएगा। इस स्थिति के बाद क्रमशः मैथैमेटिक्स, फिजिक्स एवं

कैमेस्ट्री के सही एवं गलत उत्तरों के नम्बर के अनुपात को देखा जाएगा। उपरोक्त सभी स्थितियों में टाई लगने पर विद्यार्थियों की एक समान आल इंडिया रैंक जारी कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में जिन विद्यार्थियों का परफेक्ट स्कोर 300 में से 300 है, उनकी एआईआर-1 जारी होगी।

ऐसे जारी होगी ऑल इंडिया रैंक:- अमित आहूजा ने बताया कि जेईई-मेन के अप्रैल सेशन के जारी किए गए परीगमनों में विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक के साथ-साथ एडवांसड परीक्षा देने की पात्रता भी जारी की जाएगी। ऑल इंडिया रैंक जारी करने के लिए

विद्यार्थियों के जनवरी एवं अप्रैल सेशन के हाँथर एनटीए स्कोर को लिया जाएगा। 7 डेसीमल में हायर एनटीए स्कोर के आधार पर ही ऑल इंडिया रैंक जारी की जाएगी। ऑल इंडिया रैंक के साथ-साथ विद्यार्थी जिस कैटेगरी से संबंधित है, उसकी कैटेगरी रैंक जारी होगी। विद्यार्थी के जनवरी एवं अप्रैल के 7 डेसीमल में हायर एनटीए स्कोर के आधार पर एडवांसड देने की पात्रता जारी की जाएगी। एडवांसड देने की पात्रता कैटेगरी के आधार पर अलग-अलग होगी। जेईई-मेन के आधार पर शीर्ष चुने हुए करीब ढाई लाख विद्यार्थी ही एडवांसड देने के पात्रता होंगे।

फैक्ट्री में लगी आग

टोंक। कोतवाली क्षेत्र स्थित निजाम बीड़ी फैक्ट्री के वर्कशॉप में बुधवार को अचानक आग लग गई, जिससे वर्कशॉप में रखी बीड़ी के बंडल (पैकेट) जलने लगे तथा धुंआ खिड़कियों आदि से निकल लगा तो अफरा-तफरी मच गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगो ने पुलिस और दमकल को सूचना दी।

बीकानेर में बीते चौबीस घंटे में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। दोपहर दो बजे के आसपास पारा उच्चतम स्कोर पर पहुंचे रहा है, वहीं शाम होते-होते कुछ राहत मिलती है। तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा।

बीकानेर में फिलहाल किसी तरह का परिचमवी विशोष का प्रभाव नहीं है। ऐसे में तापमान भी कम नहीं होगा। सोमवार की रात राज्य में सबसे गर्म बीकानेर में रही। जब पारा 28.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था।

भीलवाड़ा । शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की आजाद नगर कॉलोनी में स्थित कुम्भा सर्किल के निकट बस्ती के बीच संचालित टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री में बुधवार दोपहर अचानक आग लग गई।

भीलवाड़ा । शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की आजाद नगर कॉलोनी में स्थित कुम्भा सर्किल के निकट बस्ती के बीच संचालित टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री में बुधवार दोपहर अचानक आग लग गई।

आग से जले टायरों से उठा धुआं देख क्षेत्र में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची 4 दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री संचालक के उदयपुर गये होने से नुकसान का आंकलन नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री हिम्मत सिंह राठौड़ व रणजीत सिंह राठौड़ की आजाद नगर में कुंभा सर्किल क्षेत्र में सम्राट टायर के नाम से टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री है।

बताया गया है कि दोनों भाई मां का उल्चार करवाने उदयपुर गये हुये थे। फैक्ट्री में वंकर काम कर रहे थे।

एक ही रात में चोरों ने आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की नकदी पर किया हाथ साफ

कृषि उपज मंडी समिति तथा सब्जी मंडी में संचालित दुकानों के तोड़े ताले

- सीसीटीवी कैमरे में कैद नकाबपोश चोर।**

खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों में भय का माहौल है और उन्होंने मंडी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। लगातार हो रही चोरियों से मंडी व्यवसायियों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी में मंगलचंद मोतीराम फर्म के मालिक मोतीराम ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान के ताले तोड़कर 37 हजार आठ सौ रूपए चुरा ले गए। भागीरथमल मोहनलाल फर्म के राकेश सैनी ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान से 7 हजार, बालाजी फ्रूट सब्जी

मर्चेट के व्यापारी खेमराज सैनी ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर 30 हजार रूपए, श्री श्याम फ्रूट कंपनी के व्यापारी सुनील ने बताया कि उसकी दुकान का ताला तोड़कर 17 हजार रूपए और व्यापारी गिरधारीलाल ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान में रखे गल्ले से 15 हजार रूपए चुरा लिए।

वहीं कृषि उपज मंडी समिति में स्थित अनाज व्यापारी बनवारी लाल चौधरी की दुकान से चोर करीब 40 हजार रूपए की नकदी चोरी कर ले गए। इधर चोरी की सूचना के बाद मौके पर एएसआई मालाराम, कांस्टेबल राजवीर सिंह पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

स्मैक सप्लायर्स गिरफ्तार

क़रौली । क़रौली के लांगरा थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीएएस एक्ट के तहत तीन स्मैक सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है।

लांगरा थाना अधिकारी वासुदेव बसवाल ने बताया कि आरोपियों कि प्रवास आकाश कुमार गर्ग,गोपेश और धर्मी माली के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी थाना कोतवाली क़रौली क्षेत्र में दर्ज मामले के आधार पर की गई। पुलिस ने गुप्त सूचना पर भट्ठा तिराहा क़रौली में घेराबंदी कर तीनों को पकड़ा। पूर्व में गिरफ्तार गजब्री प्रजापत और रवि उर्फ सत्यनारायण कि निशानदेही से यह कार्यवाही कि गई। आरोपी रवि से स्मैक खरीदकर छोटी-छोटी पुडियों में बांटते थे। फिर इसे क़रौली,मांसलपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाइ करते थे। इनका स्मैक का मुख्य ख़ौत गंगापुर सिटी बताया जा रहा है। थानाधिकारी वासुदेव प्रसाद जाेने के नेतृत्व में यह कार्यवाही कि गई।

बीकानेर में कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर महिला से दुष्कर्म

- पीड़ित महिला ने कोर्ट से इस्त्ताफ़ा से के आधार पर गंगाशहर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।**

बीकानेर। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने कोर्ट से इस्त्ताफ़ा से के आधार पर गंगाशहर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिवार को मकान निर्माण के लिये रुपयों की जरूरत थी। महिला अपने ही समाज के अचलाराम सांसी निवासी बायतु, बिंजाराम सांसी और उसके भाई ताजाराम सांसी से मिली।

आरोप है कि रुपए देने का झांसा देकर उन्होंने महिला को जोधपुर बुलाया। वहां से उसे अहमदाबाद ले गए। जहां कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया। उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म

किया। इसके बाद उसे बालोतरा में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस के अनुसार यह घटना पिछले साल 27 दिसम्बर से 31 दिसंबर के बीच की बताई जाती है। गंगाशहर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गफलत में मरीज के अटेंडेंट को ओ.टी. में ले जाकर लगा चीरा, मचा हड़कंप

घटनाक्रम के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है

- तीन सदस्य जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है**

इसके बाद स्टॉफ उसे अंदर ले गया और ऑपरेशन थिएटर पर टेबल पर लेटा दिया।

उसके हाथ में फिस्टुला बनाने के लिए चीरा भी लगा दिया गया। इसी दौरान उसके बेटे का इलाज कर रहे डॉक्टर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यह तो उनके मरीज का अटेंडेंट है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद इस मरीज के वापस टांके लगाए गए। उसे ओटी से वापस उसके बेटे के बाई में भेज दिया। बाद में जिस मरीज का डायलिसिस फिस्टुला बना था उसका फिस्टुला बनाया गया।

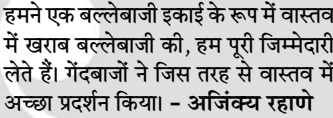
जिस अटेंडर के साथ यह घटना हुई है वह पैरालाइड्ड है। वह ठीक से बोल नहीं पाता है। इसीलिए जब उससे पूछा गया तो वह कुछ भी नहीं बोल

पाया और डॉक्टर ने भी प्रोसीजर शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। ओटी में मरीज को ले जाने के पहले उसे ओटी की ड्रेस पहनाई जाती है लेकिन इस मरीज ने ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी। दूसरी तरफ हाथ में डायलिसिस फिस्टुला बनाने के लिए बाल हटाए जाते हैं और सफाई की जाती है वह भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया। यह काफी छोटा प्रोसीजर था इसलिए डॉक्टर ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मामले को लेकर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. विकास खंडेलिया का कहना है कि मरीज को जिला के बाईर दूरे मरीज के अटेंडेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के संबंध को सूचना मिली है। कई तरीके की जानकारीयां सामने आ रही हैं। जांच के लिए तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

4.24 लाख टन बजरी का अवैध खनन

बीकानेर। यहां अवैध खनन की सूचना पर जिला कलेक्टर की ओर से गठित एएसआईटी. दल ने ग्राम झ़झू के पास बजरी का अवैध खनन पकड़कर 19.11 करोड़ रुपए की पेनल्टी तय की है। एसआईटी मौके पर पहुंची तो दो अलग पीटो में अवैध खनन किया जा रहा था। टीम को देख कर मौके से अवैध खनन करने वाले लोग भाग निकले। मौके पर देखने पर दो एक्सकैवेटर मशीनें एवं तीन डंपरों को जब्त किया गया ।

मौके पर कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी झ़झू को बुलवाया गया। दोनों अवैध खनन के पीट वाली भूमि के खतेदार उदाराम, कोजाराम, मानाराम मेघवाल, पप्पूराम सांसी, पाबूराम नायक हैं । मौके पर देखने पर दो एक्सकैवेटर मशीनें एवं तीन डंपरों को जब्त किया गया । मौके पर अवैध खनन का नाप किया आगे जिसके अनुसार इन दोनों पीटो से कुल 4.24 लाख टन बजरी का अवैध खनन हुआ जिसपर कुल रूपए 19.11करोड़ की पेनल्टी तय की गई है। तहसीलदार कोलायत दोनों खतेदारी भूमियों को आराजीराज करेंगे।



**सुरुचि ने स्वर्ण, मनु
भाकर ने रजत और सौरभ
ने जीता कांस्य पदक**

क्रमाश्रयः स्वर्ण और रजत पदक जीतो वहाँ सोरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सुरुचि सिंह ने मंगलवार को फाइनल मुकाबला जीतने के लिए कुल 243.6 अंक हासिल किए और दो बार की ऑलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को शिकस्त दी, जो 242.3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जबकि पुष्पलत रिपब्लिक ऑफ चाइना की याओसी कान्गक्सन ने 219.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान हासिल किया। यह सुरुचि सिंह का विश्व कप में दूसरा स्वर्ण पदक है। उन्होंने पिछले सप्ताह आईएसएसएफ विश्वकप 2025 ब्यूनस आयर्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। पिछले वर्ष नई दिल्ली में शूटिंग नेशनल में सात स्वर्ण जीतने वाली सुरुचि ने ब्यूनस आयर्स में फाइनल में 244.6 का स्कोर बनाकर पहला विश्व कप पदक अपने नाम किया। सुरुचि सिंह और सोरभ चौधरी ने ब्यूनस आयर्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक भी जीता था। 578 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में सातवें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने वाले सोरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कुल 219.1 अंक हासिल कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रतिस्पर्धा में चीन के हू काई ने स्वर्ण और ब्राजील के फेलिप अल्मेइदा वू ने रजत पदक मिला।

का बल्ला जांच में फेल रहा। आईपीएल के 31वें मुकामले में मंगलवार को रिजर्व अंपायर सैयद खालिद ने कोलकाता नाइट राइडर्स की साथी शुरु होकर पर सलामी बल्लेबाज नारायण का बल्ला जांचा गया। जांच के दौरान बल्ले की चौड़ाई को एक सेंटी के बीच से गुजारा गया। उनका बल्ला सफेस मोटा हिस्सा गेज को पार करके में विकल रहा। इस दौरान खालिद ने नारायण के साथ खड़े राखुवंशी का बल्ला भी गौर से देखा। राखुवंशी का बल्ला इस जांच में पास रहा। पहली पारी के दौरान तला ओवर में 14 रन देकर दो विकेट लेते वाले नारायण ने अपनी पारी में चार गेंदों में पांच रन बनाए। वहीं राखुवंशी केकेआर की ओर से 28 गेंदों में 37 रन बनाकर शोरी स्कोरर रहे। केकेआर की ओर से नॉट आउट अंतिम बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे लोकन वर जिस बल्ले के साथ मैदान में उतरे थे उसे वापिस भेज दिया गया क्योंकि टीवी कॉमेंटरेटर के अनुसार अंपायर्स मोहित कृष्णदास और साईदर्शन कुमार की जांच में उनका बल्ला फेल हो गया। यह घटना 16वें ओवर में हुई, इसके बाद सब्सटि्यूट र हमाहनउल्लाह गुरबाज नॉट आउट के लिए अतिरिक्त बल्ले लेकर आया। हालांकि वह इस बल्ले से एक भी गेंद नहीं खेल पाये स्ट्राइक पर खड़े आंद्रे रसल आलही हो गेंद पर बोल्ड आउट हो गये।

उल्लेखनीय है कि नियमों के अनुसार किसी भी बल्ले की चौड़ाई 10.79 सेमी, मोटाई 6.7 सेमी, किनारे की चौड़ाई चार सेमी तथा लंबाई 96.4 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने इतिहास रच दिया है। करमसल, टीम ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। इस दौरान मोहन बागान ने बैंगलुरु एफसी को हराया है। उसने ये मुकाबला 2-1 से जीता। वहीं मोहन बागान संजोय गायेनका की टीम है। इस जीत के साथ ही आईएलपीटीएम लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टीम को बशर्त दी है।आईएसएल के इस सीजन का फाइनल मैच कोलकाता के साएट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। मोहन बागान ने फाइनल मैच के खिलाफ से ही आक्रामक खेल दिखाया। टीम के दमदार खिलाड़ी दिमित्री पेद्रोटोस ने 29वें मिनट में गोल करके बढ़त दिला दी। लेकिन जवाब में बैंगलुरु ने भी कराार जवाब दिया। उसके ये पहले हाफ में एक भी गोल नहीं कर सके। मोहन बागान के गोलकीपर विशाल कैथी ने इस दौरान कमाल का प्रदर्शन किया।बैंगलुरु एफसी ने दूसरे हाफ में 40वें मिनट में सुनील छेत्री ने टीम को सराबोरी पर पहुंचा दिया। छेत्री ने 62वें मिनट में हेडर के जरिए गोल दगा था। उसके लिए जेसन क्रॉस ने 78वें मिनट में गोल करके बड़ दिला दी। इस तरह मोहन बागान ने मुकाबला 2-1 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया।



नई दिल्ली, 16 अप्रैल। दिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करी हुए अरुण जेटली स्टेडियम में 20 ओवर में 5 विकेट के साथ 188 रन बनाए, इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम भी 20 ओवर में 4 विकेट छोड़कर 188 रन बना सकी। सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 5 गेंद में 11 रन बनाए। उसके दोनों बल्लेबाज रन आउट हुए। दिल्ली ने चौथी गेंद पर ही ट्रागेडि हासिल करके जीत हासिल की।

189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम को संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि 31 के निजी स्कोर पर वह चोट के कारण रिटाइरेंड हट हो गए। संजू ने 19 गेंद में 31 रन बनाए। रियान पराग 11 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंद में 51 रन की पायी खेली। ध्रुव जुरेल 17 गेंद में 26 रन बनाकर रन आउट हुए। हेतमायर ने 9 गेंद में 15 रन बनाए।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तीसरे ओवर में पहला झटका लगा। फ्रेजर मैक्कार्क 6 गेंद में 9 रन ही बना सके। करुण नायर रन आउट होकर पबलिसन लौटे। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल के बीच तीसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी हुई। राहुल 32 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक पोरेल 37 गेंद में 49 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान अक्षर पटेल ने 14 गेंद में 34 रन बनाए। दिव्यन स्टम्भ 18 गेंद में 34 रन और आशुतोष 11 गेंद में 15 रन बनाकर नाबाद लौटे। राजस्थान की ओर से जोश्रा आर्चर ने दो, तीक्ष्णा और हसरंगा ने 1-1 विकेट लिया।

बैंगलूर, 16 अप्रैल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को भारतीय सीनियर महिला टीम के लिए मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट और स्टैंड-इन कंडीशनिंग कोच के लिए आवेदन पर आमंत्रित किया है। बीसीसीआई ने बैंगलूर में स्थित बीसीसीआई ऑफ एक्सलेंस में मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट और स्टैंड-इन कंडीशनिंग कोच के लिए आवेदन मांगे हैं। इनके बाद कोच और मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट को मैच रन-द्यूटी में दौड़ाना सीनियर महिला टीम के साथ करना भी आवश्यक है। मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट को मैच के पास खेल या मरकुलोस्केटेट फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ ही कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। महिला टीम के कोच के लिए बीसीसीआई सीओई लेवल 1 (च) (या समकक्ष) जिसके पास हाई-परफॉर्मिंग एथलिटिक्स/इंटरनेशनल/इंडिया या ए/इंडिया अंडर-19/फॉर्मिंग एथलिटिक्स/आईपीएल टीम के साथ कम से कम तीन साल (अथवा) 7 वर्षों में क्रिकेट कोचिंग का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

जयपुर, 16 अप्रैल। यूएनियन क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 27वीं नवीन-क्रीडा स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में आज सोनी क्रिकेट ग्राउंड कालवाड़ रोड, जयपुर में खेले गये पुल-डी के मैच में सचिन तेंडुलकर 7 रन पर 7 विकेट की नायाब 6 बराबरी तथा अफरीस खान 61 रन नाबाद अद्वर्शतकीय पारी की बराबाला बाउण्ड्री करके क्रिकेट ऐकडमी में नायागण क्रिकेट क्लडमी को 7 विकेट से हराकर 2 अंक जीत सिक्यै।

टॉप जितकर बाउण्ड्री ब्रेकर क्रिकेट क्लडमी ने पहले क्षेत्ररक्षण करते हुये नायागण क्रिकेट ऐकडमी को पहले लेलेबाजी के लिये आमंत्रित किया नायागण क्रिकेट क्लडमी की ओर से राजवीर सिंह 56 रन राजेश

फिनोवा कैपिटल ने पार्टनर के रूप में राजपुर, 16 अप्रैल। भारत की अणुगीबीएफसी में से एक फिनोवा कैपिटल को जूटा आईपीएल 2025 सीज़न के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। की मदद से फिनोवा राजस्थान रॉयल्स की तापक पहुंच और प्रभाव का लाभ उठाकर रत भर के समुदायों के साथ गहन जुड़ाव को हावा देना चाहता है। इस सहयोग के माध्यम फिनोवा कैपिटल छोटे व्यवसाय मालिकों को का यत्राओं को आगे बढ़ाएगा, वित्तीय श्रुता को बढ़ावा देगा और देश के विकास बढ़ावा देने वाली उद्यमशीलता की भावना जशन मनाएगा। ये पहल देश भर में समावेशी कास को बढ़ावा देने और उद्यमियों को सशक्त ाने के फिनोवा के मुख्य मिशन को दर्शाएंगे।

मौलाना के संस्थक का पीछा करने
अतः यथानुसार कोठी को संजु
कराया गया। यशस्वी जायसवाल ने
आतंनिकी दिलाई। हालांकि 31 के
र पर वह चोट के कारण
के बीच तीसरे विकेट के लिए
र बनाकर आउट हुए। यशस्वी
ने 37 गेंद में 51 रन के
ध्रुव जुजेल 15 गेंद में 26
रन आउट हुए। हेटमयार ने
5 रन बनाए।

बल्लेबाजी करने उतरी
कोठी को तीसरे

आवर में पहला इ
मैकगर्क 6 गेंद में 3
कराय नया रन अ
लौटे। केएल राहुल
के बीच तीसरे विकेट के लिए
के बीच तीसरे विकेट के लिए
र बनाकर आउट
37 गेंद में 49 रन के
कप्तान अक्षर पटेल
र बनाए। दिनेश स
र और आशुतोष
ने बनाकर नाबाद
से जोफ्रा आर्चर ने
हरसंग ने 1-1 वि

जयपुर, 16 अप्रैल आरसीएडहॉक कमेटी संयोजक व विधायक जयदीप बिहानी के अनुसार मध्य क्षेत्र राजस्थान अंडर 14 टीम का चयन राजस्थान जूनियर चयन कमेटी ने किया। विहार में बताया की मध्य क्षेत्र राजस्थान अंडर 14 टीम में भाग लेने वाली राजस्थान टीम के संभावितों के चयन हेतु	जयपुर आयोजित शिविर वाले जूनियर अंडर 14 आयोजित राज जयपुर उत्तराखण्ड
--	--

दामार 39 रन तथा मनीष 24 रन की पारियों में बाउण्डरिज सचिन चौधरी 7 रन पर 7 विकेट ने उन्नती की चौधरी पर लगाम लगाते हुये स्कोर 20 ओवर में 9 विकेट पर 140 रन तक सीमोंत कर दिया। जवाबी पर 140 में अफसोस खान 61 रन नाबाद (48 गेंद, 9 चौके), प्रतीर ब्रन्जानी 27 रन, कोस्तूष नबाना 26 रन, रजत गुजरानी 27 रन बढा देने में मिकलर विजय लक्ष्म 142 रन 3 विकेट खोरक 17.5 ओवर में हासिल कर 7 विकेट से जीत हासिल कर ली, नारायण एकेडमी की ओर से भूवन बागवान, राजवीर सिंह व रोहित चौधरी प्रत्येक 1-1 विकेट ले कर सफल गेंदबाज हैं। मैने ओवर द मैच सचिन चौधरी 7 रन 7 विकेट कर बाउण्ड्री ब्रेकर क्रिकेट एकेडमी रहे।

ईपीएल 2025 के लिए स्थान रॉयल्स के साथ

का लगा। फ़ेजर
होकर बना सके।
पबेलियन
पर अधिक पारेल
के लिए 63
लाल 32 गेंद 38
अधिक पारेल
नाकार और हुआ
ने 14 गेंद में 34
स 18 गेंद में 34
गेंद में 15
रसस्यार का और
दो, तीक्ष्ण और
लिया।

अंडर 14 मध्य क्षेत्र राजस्थान इंद्रापुर ट्रॉफी हेतु घोषित राजस्थान टीम : खुबचत सिंह चौहान (कप्तान) कोस्तुबधनकड्ड (उपकप्तान), वशिष्ठ शर्मा (विकेट कीपर), अभिमानु चौधरी, अनमोल, गौरव डंगार, हिमांशु जज्जवा, कृष्णाचौधरी, लक्ष्यमराठौर, माधव गोपाल गौतम, निधीश राज, रिहानखान रेयानसेबैस्टियन, सचिन मीणा, विवेक बागड़ी, यतीश जोहररा।

सुरक्षित खिलाड़ी : अश्वर्ध माल्लू शौर्य प्रताप सिंह, यशवंत सिंह, दशरथ सेटियासमोर्ट स्ट्राफ : धीरज शर्मा - हेमंत कोच व मैनजर, रवि प्रकाश - कोच अजहदहैन - कोच, अकाशा वशिष्ठ फिजियो, लोकेंद्र सिंह - ट्रेनरायी दिनांक 17 अप्रैल को देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगी।

जयपुर, 16 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय वुश महासंघ के तत्वावधान में दिनांक 06 से 10 अप्रैल 2025 तक जियांगिंगन, चीन में आयोजित हुई,

**ए ऑफिशियल
हाथ मिलाया**

से जुड़ने और उद्यमियों और युवाओं करने के लिए रोमांचक नए तरीके

ता सहानी और सुनीता सहानी द्वारा स्थापित, फिनोवा कैपिटल का तेजी हुआ है। 16 राज्यों में 450 से अधिक का संचालन, समावेशी विकास ध्यान केंद्रित सूक्ष्म, लघु और मध्यम लिए समाधान इस साझेदारी के माध्यम कैपिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा ए राजस्थान रॉयल्स के शक्तिशाली लाभ उठाएगी और पूरे भारत में छोटे मालिकों की प्रेरक यात्रा को बढ़ावा ए राजस्थान रॉयल्स के शक्तिशाली का लाभ उठाएगी। इस सहयोग ता की भावना और लचीलेपन का ने है उद्देश्य से डिजिटल अभियान, ने की सामग्री और जमीनी स्तर पर शामिल होंगे।

कार्य

आजाराई
अमृत महोत्सव

पी.एच.डी.डी. कैम्पस, इ
फोन-0151-2226475 ई-मेल-

क्रमांक-51-59

Bid for various works are invited to register procurement portal www.sppp.rajabhaskar.com 274.47 lacs.

NIT No.	1	2
UBN No.	PHE2526 WSCB00657	PHE2526 WSCB00657
NIT No.	9	10
UBN No.	PHE2526 WSCB00657	PHE2526 WSCB00657

DIPRC/5121/2025

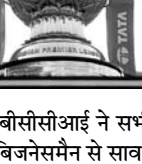


लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में
सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। ऋषभ
में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अभी तक
चार जीत दर्ज की हैं। तेज गेंदबाजी में श
अलावा लखनऊ के लिए कोई अन्य

क्या आप जानते हैं ?... आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें 15 जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम थोड़ा आगे है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने 14 जीत दर्ज की है।

राष्ट्रदूत, अजमेर 17 अप्रैल, 2025 **5**

आईपीएल 2025 पर फिक्सिंग का साया, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और स्टाफ को सावधान रहने की दी चेतावनी



नई दिल्ली, 16 अप्रैल

बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 की सभी 10 टीमों को चेतावनी दी है। दरअसल, चेतावनी में ये बताया गया है कि हैदराबाद का एक बिजनेसमैन गैरकानूनी काम करवाने के लिए लोगों से संपर्क कर रहा है। एक मॉडियारिपोर्ट

अनुसार बीसीसीआई ने सभी क्रिकेटर्स, कोच, कमेंटेटर और स्पॉटर्स स्टाफ को भी इस बिजनेसमैन से सावधान रहने की चेतावनी दी है। बताया गया है कि बिजनेसमैन कई सारे बुकी के संपर्क में है। ये व्यक्ति टूर्नामेंट में लोगों को महंगे महंगे गिफ्ट देकर अपनी बात मनवाना है। क्रिकेटरों की रिपोर्ट के अनुसार बिजनेसमैन आमतौर पर सबसे पहले टीम मालिक, खिलाड़ी, कोच, स्पॉटर्स स्टाफ और यहां तक कि कमेंटेटरों के परिवार के सदस्यों से संपर्क में आने का प्रयास करता है। एंटी करप्शन यूनिट का मानना है कि ये व्यक्ति पहले भी गैरकानूनी गतिविधियों से सम्मिलित रहा है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि, हैदराबाद का ये बिजनेसमैन मैदानों में फैन बनकर आईपीएल में भाग ले रहे खिलाड़ियों कोच और कमेंटेटरों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है। उसे टीमों के होटल, मैदान में भी देखा जा चुका है। वो खिलाड़ियों और स्टाफ को डाइनेट पार्टी में आमंत्रित करता है और ज्वेलरी समेत कई महंगे-महंगे गिफ्ट देता है। बोर्ड ने इस संदर्भ में आईपीएल 2025 में भाग ले रही सभी टीमों और उनके लिए खेल रहे खिलाड़ियों से साथ मांगा है। बीसीसीआई मैच फिक्सिंग बीसीसी घटनाओं के बिजुल्लु खिलाफ है और क्रिकेट की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रमाणिका-ननिको उ./चि/यो/2025/08-14 दिनांक 09.04.2025

--: इ-निविदा सूचना :-

नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा किसी भी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों में निम्न कार्य को करने वाले अनुमति संकेतकों से ई-निविदा पद्धति की ओर प्राय लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यों की अंतिम तिथि, निविदा खेद जाने, प्राप्त करने, अन्य शर्त एवं जानकारी की जाती है वेबसाईट www.kotamco.gov.in, www.spppr.rajjasthan.gov.in & [www.eproc.rajjasthan.gov.in](http://eproc.rajjasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है।

(अनुमानित राशि 38.92 लाख रुपये)

NIB Code – DLB2526A0364
UBN – DLB2526W8RC01486
राज.सं.चांदा/सी/25/512

अधिशासी अधिकृत (लिफ्ट)
नगर निगम कोटा उत्तर

Notice Inviting Bid

श्रेष्ठ में विभिन्न स्थानों पर दिवार डिजाइन पेंटिंग का कार्य, बीडा के बीकेटी क्षेत्र में पप्प या देवर का कार्य, बीडा की प्रस्तावित बाबाजी आवास योजना नीमराग की कारोदरी सीमा का निर्माण कार्य, समतल चोक से नीला चोक के मध्य आसोरीसी नाल, डिवाइड्ड मरुतम ग्रेड क्रुपपाय निर्माण का कार्य" is invited from interested Bidders up to 12.00 Noon Date 23.04.2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal <http://eproc.rajjasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in> of the state; and <https://bida.rajjasthan.gov.in> in departmental website.

UBN : BDA2526WSOB000003, BDA2526WSOB000004, BDA2526WSOB000005, BDA2526WSOB000006, BDA2526WSOB000007

Raj.Samwad/C/25/8100 **Executive Engineer**

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

निम्नालिखित कार्यों के लिए अनुभवी कंसल्टेंट फर्मों से निर्धारित प्राइज में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (₹.)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Tender for Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report for Development of Tourist Facilities and Parikrama Marg for Brij Chourasi Kos in the state of Rajasthan. UBN / RFP Code: HPP2526GRFP001	65.00 Lakh	3 Months

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raja.nic.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक निविदादाताओं को अपने निजीटेल इन्स्टांसार के माध्यम से वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

तला. संख्या/बी/25/816

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ला ग्रामीण खेड द्वितीय, बीकानेर

न हरिया, के.जी. कॉम्प्लेक्स के पास, रानीबाजार, बीकानेर (334001)

driibika@gmail.com, eediv2.bik, phed@rajasthan.gov.in Latitude

28.005250 Longitude 73.3249120

Inviting Bid :- 01 to 16/2025-26 दिनांक-04.04.2025

Interested bidder upto 21-04-2025 at 18.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the

link "http://proc.rajasthan.gov.in" of the state. The approximate value of the procurement of Rs.

3	4	5	6	7	8
PHE2526 WSOB0660	PHE2526 WSOB0661	PHE2526 WSOB0662	PHE2526 WSOB0664	PHE2526 WSOB0665	PHE2526 WSOB0666
11	12	13	14	15	16
PHE2526 SOB00669	PHE2526 WSOB0670	PHE2526 WSOB0671	PHE2526 WSOB0672	PHE2526 WSOB0673	PHE2526 WSOB0674

(नरेश कुमार रॉय) अधीशाषी अभियंता
जला स्वच्छता अभियंताधिकृत विभाग,
जिला ग्रामीण खेड-11, बीकानेर

‘पुलिस की वर्दी एक कपड़ा नहीं, जीवन का अर्थ है’

■ मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मैस भत्ता व वर्दी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की तथा सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की।

■ भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस स्थापना दिवस पर आरसीए में परेड का निरीक्षण किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी एवं कार्मिकों को पुलिस पदक तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिये।

माल की सुरक्षा करते हैं। शर्मा बुधवार को राजस्थान पुलिस अकैडमी (आर.पी.ए.) में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद

समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है।

मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर

कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के वर्दी भत्ते को 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने तथा पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये करने की घोषणा की। शर्मा ने कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अलावा, सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा भी की। शर्मा ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है। उन्होंने कहा, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गांवों-मोहल्लों में बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने परेड ग्राउंड में परेड निरीक्षण किया। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को पुलिस पदक तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए।

पुलिस महानिदेशक यू आर साहू ने बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर बजट में की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

अमेरिकी जज ने भारतीय छात्र का निर्वासन रोका

वाशिंगटन, 16 अप्रैल। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रम्प प्रशासन को एक भारतीय स्नातक छात्र को निर्वासित करने से रोक दिया है, जिसका स्टूडेंट वीजा उसके स्नातक होने से कुछ ही हफ्ते पहले चार अप्रैल को रद्द कर दिया गया था। मैडिसन अदालत के डिस्ट्रिक्ट जज विलियम कॉर्नले ने कहा कि यूडब्ल्यू-मैडिसन के अंतर्राष्ट्रीय छात्र 21 वर्षीय कृष्ण लाल इस्सरदासानी का छात्र वीजा रद्द नहीं किया जा सकता और ट्रम्प प्रशासन उसके खिलाफ निर्वासन सहित कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध मैडिसन के वकील शबनम लोतफी द्वारा किया गया था, जब सरकार के छात्र एवं विनिमय आर्गुतुक कार्यक्रम (एसईवीआईएस) डेटाबेस में इस्सरदासानी का रिकॉर्ड समाप्त कर दिया गया था।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आ गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

‘अन्नाद्रमुक चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार अन्नाद्रमुक ही बनायेगी। अब, इडापट्टी के इस बयान के बाद, भाजपा की वे सारी योजनाएं उलट-पुलट हो जायेंगी, जो उसने तमिलनाडु को लेकर बनाई थीं। भाजपा तमिलनाडु में प्रवेश करने तथा वहाँ अपनी जड़ें जमाने के लिये पिछले कई वर्षों से जी-तोड़ कोशिश कर रही है। दरअसल, अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुये, भाजपा ने, अन्नाद्रमुक को खुश करने के लिये तथा विधानसभा चुनावों के लिये उसे एनडीए के घेरे में लेने के लिये, अपने नेता, के. अन्नामलाई को भी दरकिनार कर दिया था।

अन्नाद्रमुक महासचिव पलानीस्वामी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यह गठबंधन तो केवल चुनावों के लिये है। अन्नाद्रमुक सुप्रीमो का यह रूख ऐसे समय में सामने आया है जब पार्टी के अंदर भाजपा के साथ हुये गठबंधन को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। खासकर, संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के पास होने के बाद कुछ पार्टी नेताओं के इस्तीफे भी आए हैं।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि कुछ प्रभावशाली अल्पसंख्यक नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं।

भाजपा ने अन्नाद्रमुक प्रमुख के बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह बात पक्की है कि वह इस बयान से खुश नहीं होगी। जब अन्नाद्रमुक, भाजपा के नेतृत्व वाले

एनडीए में शामिल हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गठबंधन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये “एक्स” पर पोस्ट डाली थी, “मिलकर और भी मजबूत।”

गठजोड़ की घोषणा करते हुये, केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि दोनों पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ेंगी तथा यह भी कहा था कि अन्नाद्रमुक ने कोई शर्त नहीं रखी है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था, “हमने तय किया है कि अन्नाद्रमुक, भाजपा तथा गठबंधन की अन्य सभी पार्टियाँ, तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के बैनर तले मिलकर लड़ेंगी।”

अन्नाद्रमुक भी, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक तथा भाजपा के साथ हुये गठजोड़ के परिणामस्वरूप, अल्पसंख्यक वोट के नुकसान के कारण, आशंकित एवं भयभीत हो रही है।

पिछले कुछ वर्षों में, जब-जब अन्नाद्रमुक ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है, उसका प्रदर्शन खराब ही रहा है। 2021 का चुनाव अन्नाद्रमुक ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था तथा केवल 75 सीटें जीत सकी थी, जबकि उससे पहले के चुनाव में उसे 136 सीटें मिली थीं इस प्रकार उसने सत्ता खो दी थी। 2019 तथा 2024 के लोकसभा चुनावों में अन्नाद्रमुक का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। 2024 के लोकसभा चुनावों में, वह राज्य की कुल 39 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

दादी के सामने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लौट रहे थे। अचानक बाधिन ने झाड़ियों से बाहर आकर बच्चे पर हमला कर दिया। बाधिन ने बच्चे की गर्दन को मुंह में दबाया और पहाड़ियों की तरफ ओझल हो गई।

प्रत्यक्ष घटना को देखकर दादी वहां जोर-जोर से रोने लगी और बेसुध हो गई। लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही डीएफओ और वनकर्मियों की टीम जंगल की ओर दौड़ पड़ी।

वनविभाग ने कैमरों से जांच करवाई तो बाधिन सुल्ताना झाड़ियों के बीच बच्चे के ऊपर पंजा रखकर बैठी नजर आई। वन विभाग के अधिकारी बाधिन से बच्चे को छुड़वाने के लिए मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास किए। इसके बाद वन विभाग ने पटाखों का उपयोग कर बाधिन को वहां से हटाया। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। वनविभाग ने देर शाम 4 बजकर 50 मिनट पर शव को बरामद किया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्टोर्स के दामों से अक्सर बहुत कम होते हैं, सौ की चीज दस में बेचते हैं।

यह रणनीति विशेष रूप से हानिकारक इसलिए है, क्योंकि सप्लायर लागत की बारीकी में जाकर, जिन सुपर लग्जरी बैग्स की खुदरा कीमत, उदाहरण के लिए, 34,000 डॉलर (करीब 29 लाख) हैं, उन्हें कथित रूप से केवल 1400 डॉलर में बना रहे हैं। इस खुलासे ने सोशल मीडिया में खलबला मचा दी है। लग्जरी रीटेल के मूल्य निर्धारण में बरती जाने वाली “नैतिकता” को लेकर बातें शुरू हो गई हैं तथा यह बात भी उजागर हुई है कि उपभोक्ता आमतौर पर लग्जरी गुड्स पर कितना भारी प्रीमियम देते हैं।

इन वायरल वीडियो ने तीव्र बहस छेड़ दी है, खासकर जब अमेरिका ने, वर्तमान में चीन से अमेरिका आने वाले सामान की एक विस्तृत श्रृंखला पर 145 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया

है। तथापि, चीनी सप्लायरों ने इन चुनौतियों से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है, और साथ ही साथ वो अपने सामान को अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुँचा रहे हैं। कई लोग लग्जरी आइटम्स को कम ड्यूटी वाली श्रेणियों में घोषित करते हैं, कभी-कभी तो उच्च-स्तरीय चमड़े के हैंडबैग को सीमा शुल्क कम करने के लिए एक साधारण ‘पीयू बैग’ या ‘उपहार वस्तु’ के रूप में लेबल करते हैं।

सप्लायरों ने एक और तरीका अपनाया है। पहले वो अपना सामान साउथईस्ट देशों को भेजते हैं, फिर माल को उन देशों के उत्पादों के रूप में पुनः निर्यात करके, अक्सर सबसे ऊँचे अमेरिकी टैरिफ से बच जाते हैं- एक गतिविधि, जिसे ट्रांसशिपमेंट के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए जांच बढ़ा दी है, लेकिन अनौपचारिक व्यापार चैनलों में यह

प्रथा अभी भी बनी हुई है।

इसके अतिरिक्त, कई चीनी सप्लायरों ने आयात शुल्क स्वयं वहन करना शुरू कर दिया है। इन अतिरिक्त लागतों के बावजूद, उनके लिए लाभ कमाने के लिए पर्याप्त मार्जिन रहता है, क्योंकि उन्हें लग्जरी ब्रांडिंग, विज्ञापन ओवरहेड्स और खुदरा मार्कअप के लिए धन खर्च नहीं करना पड़ता। कुछ मामलों में, सामान को बल्क कॉमर्शियल शिपमेंट के बजाय, छोटी-छोटी व्यक्तिगत खेपों के रूप में भेजा जाता है, जिससे सीमा शुल्क जांच और टैरिफ देनदारियाँ कम हो जाती हैं।

कुछ सप्लायर हांगकांग, दुबई या सिंगापुर जैसे टैरिफ-अनुकूल या कर-मुक्त क्षेत्रों में अपने गोदाम रखते हैं। इन स्थानों से वो ऑर्डर पूरा करते हैं, कभी-कभी कम शुल्क ब्रेकेट तक पहुँचने या प्रतिबंधों को पूरी तरह से बाईपास करने के लिए अपने सामान को “नॉन चाइना ओरिजिन” (गैर चीन

मूल) का रूप दे देते हैं।

वायरल हुए क्लिप चीनी उत्पादों की क्वालिटी के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग वीडियो में दिखा रहे हैं कि इन लग्जरी आइटम्स को बनाने में कितनी सावधानी बरती जाती है तथा कितनी कुशलता से इन्हें बनाया जाता है।

इसके अलावा, कितना हाई ग्रेड का रॉ मटीरियल उपयोग में लिया जाता है तथा इन्हें बनाने वाले कारीगर कितने अनुभवी हैं। ऐसा करके सप्लायर इस धारणा को भी चुनौती देना चाहते हैं कि चीन में निर्मित सामान स्वाभाविक रूप से हीन या घटिया होता है।

बीजिंग के लिए, यह जवाबी कार्रवाई उसकी व्यापक आर्थिक रणनीति के अनुरूप प्रतीत होती है। जबकि, अमेरिका दंडात्मक टैरिफ के साथ चीनी माल को लक्षित कर रहा है, चीन ने 125 प्रतिशत तक के शुल्क के

साथ जवाबी कार्रवाई की है और घरेलू सुधारों को गहरा करने और अपनी वैश्विक आर्थिक साझेदारी का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। चीनी अधिकारियों ने वाशिंगटन के ट्रेड एक्शनस को एकतरफा “दादागिरी” बताया है और दबाव की रणनीति का विरोध करने का संकल्प लिया है।

यह नया घटनाक्रम इंगित करता है कि कैसे व्यापार युद्ध बोर्डरूम और टैरिफ शीट से आगे बढ़कर सार्वजनिक और डिजिटल क्षेत्रों में चला गया है, चीनी सप्लायर, बाजार में पश्चिमी लग्जरी ब्रांडों के प्रमुख को अस्थिर करने के लिए, उपभोक्ता से सीधे जुड़ाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा करके, वे न केवल लग्जरी मूल्य निर्धारण मांडल के अंदरूनी कामकाज का खुलासा कर रहे हैं, बल्कि यह भी परीक्षण कर रहे हैं कि आर्थिक शत्रुता के माहौल में ग्रे-मार्केट कॉमर्स कितनी दूर तक फैल सकता है।

एकल पट्टा प्रकरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार ने एसीबी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व आईएएस जीएस संघू सहित, अन्य के खिलाफ लंबित मुकदमे को वापस लेने की गुहार की थी, जिसे एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एसीबी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि अभियोजन वापस लेने का पूर्व का निर्णय औचित्यहीन है और मौजूदा राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केस को आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि यदि जांच में कोई कमी, गलती है या जांच दोषपूर्ण है तो वह न्याय के लिए उस संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय पर

भी पुनर्विचार कर सकती है। इसलिए उन्हें रिवीजन याचिका वापस लेने की मंजूरी दी जाए इस दौरान आरोपी पक्ष की ओर से मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस राठौड़ की कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाया गया।

गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने वाले अशोक पाठक को हाईकोर्ट में पक्षकार बनाए जाने के मुद्दे पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दरअसल राज्य सरकार ने इस मामले में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि एसीबी कोर्ट के समक्ष दायर क्लोजर रिपोर्ट अधूरी व दोषपूर्ण साक्ष्यों पर की गई जांच के आधार पर पेश हुई थी। इसके चलते ही पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को राहत मिली थी।

इस बेमिसाल अवसर को हरगिज़ न गवाएं! जल्दी करें!

अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी एरीना कार पर जबर्दस्त ऑफ़र्स पाएं .

3 years

100 000 km WARRANTY**

EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

विशेष ऑफ़र

ALTO K10 ₹68 100* | S-PRESSO ₹63 100*
WAGONR ₹68 100* | CELERIO ₹68 100*

SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

Contact us at
1800-102-1800

T&C Apply Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black Glass Shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on selected models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on selected models. Offer valid with selected financiers only. **3 years or 100 000 km whichever is earlier. Above offers are valid till 30th April, 2025.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुभान एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हट्या, बीकानेरा। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908